

उफान पर नदियां, हाईवे तक पहुंचा पानी

● गुजरात-उत्तराखंड में स्कूल बंद, यूपी में हाहाकार ● एमपी और महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी



नई दिल्ली (एजेंसी)। यूपी में मानसून फिर से कमजोर पड़ गया है, लेकिन पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के कारण गंगा, घाघरा-सरयू समेत 10 नदियां उफान पर हैं। वहीं, बिजनौर में गंगा का पानी बहसूमा-ठाकुरद्वारा स्टेट हाईवे के ऊपर से बह रहा है। गुजरात में आज सभी स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। वहीं, उत्तराखंड में भी खराब मौसम को देखते हुए

बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में भी स्कूल बंद हैं। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में गर्मी बढ़ गई है। जैसलमेर, बाड़मेर में तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। इसकी वजह पश्चिम की तरफ से आ रही गर्म हवाएं हैं। मध्य प्रदेश में मानसून के 3 स्ट्रॉंग सिस्टम ऐक्टिव हैं। इसके चलते अगले 2 दिन प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा राजस्थान, बिहार समेत 7 राज्यों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। **गुजरात में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात-** बंगाल की खाड़ी से उठ रहे तूफान के कारण गुजरात के सूरत में प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खराब मौसम की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने संभावित नुकसान को कम करने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं।

● **अरुणाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड की चेतावनी-** मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में 31 जुलाई से भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने 9 जिलों के लिए फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ का अलर्ट भी जारी किया है। तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़कर 43 फीट पहुंच गया है। इसके बाद प्रशासन ने पहला खतरे का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं, नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए 9.32 लाख क्यूसेक पानी डाउनस्ट्रीम की ओर छोड़ा गया है। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ● **महाराष्ट्र के सतारा में लैंडस्लाइड से सड़क बंद-** महाराष्ट्र के सतारा जिले में भारी बारिश के कारण दो जगह लैंडस्लाइड हुआ। इससे

ढेबेवाड़ी-नवरास्ता मार्ग को बंद कर दिया गया। लगातार बारिश से जलस्तर बढ़ने के कारण पुराना संगमनगर पुल भी पानी में डूब गया। प्रशासन ने लोगों से बिना जरूरी काम के यात्रा न करने की अपील की है। ● **मध्य प्रदेश के खंडवा में टापू पर फंस 4 लोगों का 11 घंटे बाद रेस्क्यू-** मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में दो नदियों के बीच बने एक टापू पर चार लोग फंस गए थे। उन्हें करीब 11 घंटे लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। चारों पिकनिक मनाने गए थे। इसी दौरान अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से वे टापू पर फंस गए। राहत अभियान के दौरान ड्रोन की मदद से उन्हें भोजन पहुंचाया गया। इसके बाद बचाव दल ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

भरत एनकाउंटर में पहली गोली मारने वाला जवान गिरफ्तार

● बिहार सीएम से परिवार की मुलाकात के बाद ऐक्शन, 5 गोलियां मारी गई थीं

आरा (एजेंसी)। बिहार में भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर में बड़ी कार्रवाई हुई है। उस पर गोली चलाने वाले बिहार एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। भरत तिवारी का एनकाउंटर 17 जून को हुआ था। उसकी मां आशा देवी ने अक्षय कुमार पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी जवान को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोप है कि आत्मसमर्पण करने के बाद भरत तिवारी को सबसे पहली गोली अक्षय कुमार ने मारी थी। एनकाउंटर की जांच के दौरान कई बार बुलाने के बाद भी वह पृच्छाछ के लिए नहीं आया।



● **मां ने कहा-एसटीएफ जवान ने पहली गोली चलाई थी-** भरत एनकाउंटर में पहली गिरफ्तारी पर आशा देवी ने कहा, 'मुझे खुशी है कि पुलिस ने कार्रवाई की है। आगे भी ऐक्शन होना चाहिए। एसटीएफ, डीएसपी की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, भरत ने उनका नाम लिया था। दरोगा भी शामिल था। उसे भी गिरफ्तार करना चाहिए। सीएम ने इंसाफ दिलाने की बात कही है, मुझे उन पर भरोसा है।'

पीएम पर टिप्पणी करने वाली लड़की पर एफआईआर का विरोध

नई दिल्ली (एजेंसी)। कॉंग्रेस जनता पार्टी ने शुक्रवार को पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली लड़की रुचिका सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का विरोध किया है। प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि लड़की के खिलाफ आपराधिक केस की जगह मानहानि का केस दर्ज करना चाहिए। यह कार्रवाई मशीनरी का दुरुपयोग है। इस देश में लोग चलते-फिरते गाली देते हैं। यह अपराध कैसे बन गया। यह मामला 23 जुलाई को जंतर-मंतर का है। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान वीडियो में लड़की पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करती नजर आई थी। गाजियाबाद की रहने वाली स्मृति सिंह ने रुचिका के खिलाफ नोएडा के एक्सप्रेसवे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। जानबूझकर अपमान करने का आरोप है।

एमपी में बनेगा देश का पहला टेलीकॉम हब



भोपाल। मध्य प्रदेश अब टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। दिल्ली में मध्य प्रदेश सरकार और केंद्रीय दूरसंचार विभाग के बीच हुए एमओयू के बाद ग्वालियर में देश का पहला इंटीग्रेटेड टेलीकॉम टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। 170 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में 5जी, 6 जी और आधुनिक डिजिटल तकनीक से जुड़े उपकरण तैयार होंगे। परियोजना में शुरुआती तौर पर करीब 2000 करोड़ के निवेश और 4500 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों की घोषणा की गई है। भविष्य में यहां 8 से 9 हजार युवाओं को स्थायी रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। ग्वालियर का यह जोन देश का पहला ऐसा केंद्र होगा, जहां टेलीकॉम उत्पादों की पूरी वैल्यू चेन एक ही स्थान पर विकसित होगी। यहां प्रोडक्ट डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और एक्सपोर्ट तक की पूरी प्रक्रिया उपलब्ध होगी।

● **प्लग एंड प्ले मॉडल पर तैयार होगा जोन-** ग्वालियर में बनने वाला यह टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन प्लग एंड प्ले मॉडल पर विकसित किया जाएगा। यानी कंपनियों को यूनिट लगाने के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं पहले से उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का लक्ष्य है कि यहां आने वाली कंपनियां तेजी से उत्पादन शुरू कर सकें और मध्य प्रदेश टेलीकॉम उपकरण निर्माण का बड़ा केंद्र बन सकें। इस जोन में 5 जी और आगामी 6 जी नेटवर्क से जुड़े उपकरणों के साथ ऑप्टिकल फाइबर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस, नेटवर्किंग हार्डवेयर और सेमीकंडक्टर से जुड़े उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। यह क्षेत्र रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए है।

पीछे की जमीन पर पढ़ी गई जुमे की नमाज

● भोजशाला में 'सुप्रीम' फैसले के बाद पुलिस ने की व्यवस्था ● आसपास बैरिकेडिंग, स्थानीय लोगों ने जताई थी आपत्ति

इंदौर (एजेंसी)। धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद शुक्रवार को एक नया घटनाक्रम सामने आया। प्रशासन और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के बीच गुरुवार देर रात हुई चर्चा के बाद भोजशाला परिसर की पिछली बाउंड्रीवॉल से सटी खसरा नंबर 612 की जमीन पर जुमे की नमाज अता करने पर सहमति बनी। इसके बाद प्रशासन ने मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और पुलिस बल के साथ बैरिकेडिंग कराई। शुक्रवार दोपहर करीब डेढ़ से दो बजे के बीच मुस्लिम समाज के लोग नमाज के लिए निर्धारित स्थल पर पहुंचे। बारिश के कारण जमीन गीली होने पर वहां तिरपाल बिछाई गई। शुरुआत में करीब 10 से 15



लोग जुमे की नमाज अता करने पहुंचे। धीरे-धीरे नमाजियों का सिलसिला बढ़ते-बढ़ते 100 से ऊपर पहुंच गया। कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी के सदर अब्दुल समद एवं याचिकाकर्ता भी नमाज पढ़ने स्थल पर पहुंचे।

जगह को लेकर स्थानीय लोगों ने जताई आपत्ति- हालांकि

नमाज के लिए तय किए गए स्थल को लेकर स्थानीय हिंदू समाज के कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। दरअसल, भोजशाला के पीछे रहने वाले रहवासियों का दावा है कि यह जमीन निजी कृषि भूमि है और उसका स्वामित्व उनका है। उनका कहना है कि इस जमीन पर नमाज की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

बारिश के बीच प्रशासन ने संभाला मोर्चा

पूरे घटनाक्रम को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने भोजशाला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। दोनों पक्षों के आवागमन के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। बारिश के कारण नमाज स्थल की जमीन गीली होने पर प्रशासन की ओर से तिरपाल आदि की व्यवस्था कराई गई, ताकि नमाज के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। इस दौरान प्रशासन ने क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। यहां पर यह बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला परिसर में नियमित पूजा जारी है, जबकि मस्जिद पक्ष पिछले कुछ समय से अपने घरों या स्थानीय मस्जिदों में नमाज पढ़ रहा है। 30 जुलाई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था के तहत यह कहा था।

जिला प्रशासन (आबकारी विभाग) इंदौर द्वारा IPS School Main Campus में “नशे से दूरी है जरूरी” जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

आदित्य शर्मा

इंदौर। जिला प्रशासन (आबकारी विभाग) इंदौर द्वारा युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से संचालित जन-जागरूकता अभियान “नशे से दूरी है जरूरी” के अंतर्गत दिनांक 30 जुलाई 2026 को IPS School Main Campus, इंदौर में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष जागरूकता एवं संवादात्मक सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सहायक आबकारी आयुक्त श्री अभिषेक तिवारी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि उसके परिवार, शिक्षा, करियर एवं समाज को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। उन्होंने बताया कि अधिकांश लोग जिज्ञासा, मित्रों के दबाव अथवा दिखावे के कारण नशे की शुरुआत करते हैं, जो आगे चलकर लत का रूप ले लेती है। उन्होंने विद्यार्थियों से आत्मविश्वास के साथ “ना कहना सीखें” का संदेश देते हुए जीवन में सही निर्णय लेने, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के मादक



पदार्थों, उनके दुष्प्रभावों, नशे से होने वाले शारीरिक एवं मानसिक नुकसान, सड़क दुर्घटनाओं, अपराध तथा पारिवारिक विघटन जैसे सामाजिक प्रभावों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। साथ ही साइबर माध्यमों एवं सोशल मीडिया के जरिए फैलने वाले

नशे के प्रलोभनों से सतर्क रहने की सलाह दी। विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती सुधा पांडे ने अपने उद्बोधन में जिला प्रशासन एवं आबकारी विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान समय में ऐसे जागरूकता कार्यक्रम विद्यार्थियों के

व्यक्तित्व निर्माण एवं उन्हें नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से प्राप्त जानकारी को अपने परिवार, मित्रों एवं समाज तक पहुंचाने का भी आग्रह किया।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को “नशे से दूरी है जरूरी” अभियान की जानकारी दी गई तथा उन्हें नशे के विरुद्ध जागरूक नागरिक बनने एवं अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करने का संकल्प दिलाया गया। विद्यार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में भाग लेते हुए नशे से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका विशेषज्ञों द्वारा सरल एवं वैज्ञानिक तरीके से उत्तर दिया गया। इस अवसर पर आबकारी विभाग की ओर से सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री धर्मेन्द्र जोशी, श्री देवेश चतुर्वेदी एवं श्री जहांगीर खान, तथा आबकारी उप निरीक्षक श्री आशीष जैन, श्रीमती त्रियंबिका शर्मा एवं श्रीमती जया मुजालदे उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन विद्यार्थियों द्वारा “नशे से दूरी है जरूरी” का सामूहिक संकल्प लेने के साथ हुआ। विद्यालय के शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए इसे अत्यंत उपयोगी एवं प्रेरणादायक बताया।

चीनी स्टॉक लिमिट पर मचा विवाद कारोबारियों की बढ़ी चिंता; NFCSF ने केंद्र सरकार से नियमों की समीक्षा की मांग की

नई दिल्ली। देश में चीनी की कीमतों और उपलब्धता को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नई स्टॉक लिमिट अब विवाद का विषय बन गई है। सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी पर रोक लगाने के लिए देशभर के चीनी कारोबारियों और डीलरों के लिए भंडारण की अधिकतम सीमा तय कर दी है। इस फैसले के बाद चीनी व्यापार से जुड़े संगठनों ने चिंता जतानी शुरू कर दी है। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड (NFCSF) ने केंद्र सरकार से इस आदेश की समीक्षा करने का आग्रह किया है। संगठन का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था से न केवल चीनी कारोबार प्रभावित होगा, बल्कि चीनी पर आधारित उद्योगों के उत्पादन और आपूर्ति पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। दरअसल, केंद्र सरकार ने चीनी की कृत्रिम कमी पैदा करने, जमाखोरी और सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार अब कोई भी चीनी डीलर या व्यापारी 4000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक अपने पास नहीं रख सकेगा। इसके साथ ही यह भी निर्धारित किया गया है कि किसी भी व्यापारी के पास 30 दिनों से अधिक की आवश्यकता



के बराबर चीनी का भंडारण नहीं होना चाहिए। सरकार का यह आदेश 1 अगस्त 2026 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे बाजार में चीनी की नियमित उपलब्धता बनी रहेगी और उपभोक्ताओं को अनावश्यक मूल्य वृद्धि का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, सरकार के इस फैसले पर चीनी उद्योग से जुड़े कई संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराई है। NFCSF का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में इतनी कम स्टॉक सीमा व्यावहारिक नहीं है। संगठन का मानना है कि बड़े वितरकों और थोक कारोबारियों को रोजाना बड़ी मात्रा में चीनी की आपूर्ति करनी पड़ती है। यदि उन्हें सीमित मात्रा में ही स्टॉक रखने की अनुमति होगी तो बाजार में समय पर

आपूर्ति करना कठिन हो जाएगा। इससे खासतौर पर मिठाई उद्योग, बिस्किट निर्माता, पेय पदार्थ कंपनियां, बेकरी, कन्फेक्शनरी और अन्य खाद्य उद्योग प्रभावित हो सकते हैं, जिनकी उत्पादन प्रक्रिया पूरी तरह नियमित चीनी आपूर्ति पर निर्भर रहती है। NFCSF ने यह भी कहा है कि चीनी की मांग पूरे देश में समान नहीं रहती। कई राज्यों और बड़े शहरों में खपत काफी अधिक होती है, जहां बड़े डीलरों को सामान्य दिनों में भी हजारों क्विंटल चीनी का भंडारण रखना पड़ता है। ऐसे में 4000 क्विंटल की सीमा कई व्यापारियों के लिए पर्याप्त नहीं होगी। यदि उन्हें बार-बार चीनी मंगानी पड़ेगी तो परिवहन लागत बढ़ेगी और इसका सीधा असर बाजार कीमतों पर भी पड़ सकता है।

आज आईटीआर भरने की आखिरी तारीख, चूक गए तो भी मिलेंगे ये विकल्प



आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। यदि किसी कारणवश आप आज भी अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग निर्धारित शर्तों के साथ बाद में भी रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देता है। नियमों के अनुसार, निर्धारित समय सीमा चूकने वाले करदाता 31 दिसंबर 2026 तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए अतिरिक्त शुल्क और ब्याज देना पड़ सकता है। यदि रिटर्न समय पर दाखिल नहीं किया जाता है, तो आय के आधार पर 5,000 तक का विलंब शुल्क देना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि कोई

कर बकाया है, तो उस पर प्रति माह 1 प्रतिशत की दर से ब्याज भी लगाया जाएगा।

समय पर रिटर्न दाखिल न करने से कुछ कर लाभ और घाटे को आगे समायोजित करने जैसी सुविधाओं पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए पात्र करदाताओं को अंतिम तिथि के भीतर ही रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी जाती है। कर विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अंतिम समय में तकनीकी दिक्कत या दस्तावेजों की कमी के कारण रिटर्न दाखिल नहीं हो पाया है, तो जल्द से जल्द विलंबित रिटर्न भरकर अतिरिक्त आर्थिक बोझ और संभावित कानूनी परेशानियों से बचा जा सकता है।

‘जेनरेशन गटर’ टिप्पणी के बाद कंगना रनौत के पुराने पार्टी वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की ‘जेनरेशन गटर’ टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो वर्ष 2018 के कान फ़िल्म महोत्सव के बाद आयोजित एक पार्टी का बताया जा रहा है, जिसमें कंगना नाचती और जश्न मनाती दिखाई दे रही हैं। विवाद तब शुरू हुआ जब कंगना ने कुछ प्रदर्शनकारी युवाओं और विशेष रूप से कुछ



युवतियों की आलोचना करते हुए उन्हें “जेनरेशन गटर” कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग स्वतंत्रता के नाम पर नशे, शराब और गैर-जिम्मेदार जीवनशैली का महिमामंडन करते हैं। इन टिप्पणियों के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। इसी बीच इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने कंगना के पुराने पार्टी वीडियो साझा करते हुए उन पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। वहीं उनके समर्थकों का कहना है कि किसी सामाजिक कार्यक्रम

में शामिल होना और अनुचित व्यवहार का समर्थन करना अलग-अलग बातें हैं, इसलिए पुराने वीडियो को वर्तमान विवाद से जोड़ना उचित नहीं है। बढ़ते विवाद के बीच कंगना ने सफाई भी दी। उनका कहना है कि उनकी टिप्पणी पूरे युवा वर्ग के लिए नहीं थी, बल्कि उन लोगों के लिए थी जो सार्वजनिक रूप से अभद्र भाषा और व्यवहार को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे थे। यह मामला अब केवल एक वायरल वीडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी और सोशल मीडिया पर पुराने वीडियो के संदर्भ में उपयोग जैसे व्यापक मुद्दों पर भी बहस का विषय बन गया है।

शासकीय भूमि पर कथित अवैध निर्माण को लेकर हिंदू समाज में आक्रोश, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन; कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी

दिलीप पाटीदार

सरदारपुर धार जिले के राजगढ़ क्षेत्र के दलपुरा में फोरलेन के समीप एवं धोबी घाट के पास स्थित शासकीय भूमि को लेकर विवाद गहरा गया है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग सरदारपुर स्थित एसडीएम कार्यालय पहुंचे और अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) अजमेर सिंह गौड़ को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच एवं तत्काल कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में हिंदू समाज ने आरोप लगाया कि संबंधित शासकीय भूमि ईदगाह एवं धार्मिक आयोजनों के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन वर्तमान में वहां धार्मिक स्थल की आड़ में कथित रूप से मटन-चिकन की दुकानें संचालित की जा रही हैं। साथ ही, टिन शेड लगाकर नए निर्माण कार्य किए जाने का भी आरोप लगाया गया है।

समाजजनों का कहना है कि यह गतिविधियां भूमि के मूल उद्देश्य और शासकीय नियमों के विपरीत हैं।

समाज ने इस निर्माण को जनहित व न्यायहित में पूरी तरह अवैधानिक बताते हुए तत्काल रोकने और पुराने अतिक्रमण को हटाने की मांग की



है। ज्ञापन में यह भी बताया कि जिस स्थान पर यह निर्माण किया जा रहा है, उसके ठीक पास आदिवासी समाज का मांगलिक भवन स्थित है, जहाँ इस प्रकार की मटन-चिकन की दुकानों का संचालन सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत अनुचित है।

इसके अलावा, समीप ही प्रसिद्ध मोहनखेड़ा जैन तीर्थ भी स्थित है, जिसकी पवित्रता और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यावसायिक व अवैध निर्माणों पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। हिंदू समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की

गई तो समाज चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है और किसी भी प्रकार की अनदेखी से जनआक्रोश बढ़ सकता है। ज्ञापन सौंपने के दौरान हिंदू समाज के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इनमें जितेंद्र बागड़िया, लखन पंवार, राकेश परवार, चंदन शर्मा, मोतीसिंह राठौड़, गोपाल सोनी, धर्मेन्द्र मंडलोई, राकेश सिंगार, नीलेश सोनी, भाजपा मंडल अध्यक्ष सोहन पटेल, ओंकारलाल जाट, प्रीतम ठाकुर, चिट्टू चौहान, श्रवण राठौड़, शुभम जोक्शन, रोहित यादव सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे।

कावड़ यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल ने सौंपा ज्ञापन



राजेश धाकड़

इंदौर। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल, इंदौर महानगर द्वारा पवित्र श्रावण मास में निकल रही कावड़ यात्राओं की सुरक्षा एवं सुविधाओं को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन में मांग की गई कि कावड़ यात्रा मार्ग पर संचालित मांस, मटन एवं शराब की दुकानों को सावन

माह के दौरान बंद रखा जाए, जिससे धार्मिक भावनाओं का सम्मान बना रहे तथा कावड़ यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ ही यात्रा मार्ग पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग की गई।

इस अवसर पर राष्ट्रीय बजरंग दल के शिवम् माली, रिककी वर्मा, नरेंद्र सेन, शुभम् बजरंगी, पिंटू शर्मा, रूपेश

बाथम, कैलाश बरेला, मदनलाल चौहान, कुलदीप दीक्षित, हर्ष मंगोलिया, आदर्श ठाकुर, विक्की रघुवंशी, योगेश चौहान, राजेश सूर्यवंशी, आशीष बामने, अभिषेक वेदांत आंजना, त्रिलोक चौहान, कृष्णा केर, दिनेश लोधा, दिनेश टाक, क्रिस सोलंकी, लकी चौहान, वीर प्रजापत, विजय जी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं धर्मयोद्धा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की जानकारी शिवम् माली द्वारा दी गई।

श्रावण के प्रथम सोमवार पर आस्था का महासंगम: अमझेरा से दसई तक निकलेगी भव्य कांवड़ यात्रा, हजारों शिवभक्त होंगे शामिल

दिलीप पाटीदार

दसाई। भक्ति एवं आराधना के पावन श्रावण मास के प्रथम सोमवार, 3 अगस्त को प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी चौधरी मित्र मंडल, दसाई के तत्वावधान में भव्य ‘बोल बम’ पुरुष कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा अमका-झमका माता मंदिर, अमझेरा से प्रारंभ होकर दसाई स्थित राम-रामेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचेगी, जहां भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक एवं पूजा-अर्चना की जाएगी। आयोजकों के अनुसार इस वर्ष कांवड़ यात्रा का तीसरा वर्ष है। पिछले दो वर्षों की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में शिवभक्तों के शामिल होने की संभावना है। यात्रा के दौरान पूरा मार्ग ‘हर-हर महादेव’ और ‘बोल बम’ के जयघोष से भक्तिमय हो उठेगा। कांवड़ यात्रा का मुख्य आकर्षण आकर्षक डीजे, पारंपरिक ढोल-नगाड़े तथा भगवान भोलेनाथ की मनमोहक झांकी रहेगी। शिवभक्त भक्ति गीतों और जयकारों के साथ उत्साहपूर्वक

यात्रा में शामिल होकर भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था प्रकट करेंगे। यात्रा की तैयारियों को लेकर हाल ही में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आयोजन की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में यात्रा के सुचारु संचालन, अनुशासन, सुरक्षा तथा श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। आयोजन समिति ने बताया कि कांवड़ियों के लिए फरियाली खिचड़ी, चाय, पेयजल, फल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। कांवड़ यात्रा के संचालक मनीष चौधरी ने क्षेत्र के समस्त शिवभक्तों से अधिक से अधिक संख्या में कांवड़ यात्रा में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि श्रावण मास भगवान भोलेनाथ की आराधना का विशेष अवसर है और सामूहिक कांवड़ यात्रा समाज में धार्मिक आस्था, भाईचारे एवं एकता का संदेश देती है।

सूक्ष्म चेतना तंत्र की जागृति-सहजयोग

मनुष्य का शरीर केवल मांस, अस्थियों और रक्त का बना हुआ ढांचा नहीं है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार इसके भीतर एक सूक्ष्म चेतना तंत्र भी कार्य करता है, जो हमारे विचारों, भावनाओं और आंतरिक संतुलन को प्रभावित करता है। जब यह तंत्र संतुलित रहता है, तब व्यक्ति स्वयं को अधिक शांत, प्रसन्न और ऊर्जावान अनुभव करता है।

हमारे हाथों की हथेलियाँ और उंगलियों के अग्रभाग केवल स्पर्श का माध्यम नहीं हैं, बल्कि इन्हें सूक्ष्म संवेदनाओं का भी वाहक माना गया है। सहज योग में आत्मसाक्षात्कार के पश्चात साधक अपनी हथेलियों और उंगलियों पर शीतल चैतन्य की अनुभूति कर सकता है। यह अनुभव किसी बाहरी कल्पना का नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर जागृत आध्यात्मिक चेतना का संकेत माना जाता है।

भारतीय ऋषियों और संतों ने सदियों पहले बताया था कि मनुष्य के भीतर सूक्ष्म नाड़ियाँ और ऊर्जा केंद्र (चक्र) विद्यमान हैं। जब इन केंद्रों में संतुलन बना रहता है, तब मानसिक और भावनात्मक स्थिरता भी बढ़ती है। सहज योग की ध्यान पद्धति का उद्देश्य इसी आंतरिक व्यवस्था को संतुलित करना है। नियमित ध्यान के दौरान यदि किसी चक्र में असंतुलन हो, तो उसकी अनुभूति हथेलियों या उंगलियों में गर्माहट, झनझनाहट अथवा अन्य सूक्ष्म संकेतों के रूप में हो सकती है। सहज योग का मूल आधार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर आत्मा विद्यमान है और उसी के माध्यम से परम चेतना का अनुभव संभव है। जब आत्मसाक्षात्कार प्राप्त होता है, तब व्यक्ति अपने भीतर प्रवाहित होने वाली शीतल चैतन्य ऊर्जा का अनुभव करता है। यह अनुभव न केवल आत्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में भी सहायक



बनता है। ध्यान के नियमित अभ्यास से व्यक्ति तनाव, क्रोध और अनावश्यक मानसिक अशांति पर नियंत्रण पाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। साथ ही वह अपने विचारों को अधिक स्पष्टता से देखना और स्वयं के भीतर संतुलन बनाए रखना सीखता है। सहज योग में यह भी माना जाता है कि सकारात्मक चैतन्य का प्रभाव हमारे परिवार, समाज, प्रकृति तथा आसपास के वातावरण तक फैल सकता है। सहजयोग एक सरल और सहज अभ्यास है, जिसे किसी भी आयु, धर्म व संप्रदाय का व्यक्ति सीख सकता है। सहज योग पूर्णतः निःशुल्क है। अपने निकटतम सहज योग ध्यान केंद्र की जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 1800 2700 800 अथवा www.sahajayoga.org.in पर संपर्क किया जा सकता है।

गुरु पूर्णिमा पर ओंकारेश्वर में महामंडलेश्वर भोला दास जी महाराज का लिया आशीर्वाद



महू (इंदौर)। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं ने महामंडलेश्वर भोला दास जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर धर्म लाभ लिया। जुगनू जादवसिंह धनावत ने

बताया कि वे अपने पूरे परिवार के साथ ओंकारेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि गुरुदेव से सनातन धर्म का जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, वह अत्यंत प्रेरणादायक और अद्भुत है। उनके श्रीमुख से गुरु वचन सुनने का अवसर मिलना स्वयं को सौभाग्यशाली मानने जैसा है। इस अवसर पर तुलसीखेड़ी के पटेल हरिसिंह मीणा द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महेंद्रसिंह मीणा, त्रियुगी जोनवाल, उमरावसिंह धनावत, जुगनू जादवसिंह धनावत, अशोक मीणा, कन्हैयालाल पटेल, आकाश मीणा, सरदारसिंह मीणा, लोकेश धनावत, जयवर्धन सिंह मीणा, धीरज मीणा, शिवा मीणा, विकास मीणा, शिवमसिंह धनावत सहित सैकड़ों श्रद्धालु, माताएं एवं बहनें उपस्थित रहीं।

तुकईथड़ में जलभराव पर प्रशासन हरकत में आया, जेसीबी से शुरू कराई पानी निकासी

नायब तहसीलदार रविंद्र मंडलोई तहसीलदार सुनील बागुल स्वयं पहुंचे मौके पर, खकनार थाना पुलिस की मौजूदगी में चला राहत अभियान

महेन्द्र मालवीय रणाजीत

बुरहानपुर। ग्राम तुकईथड़ में जलभराव के कारण आंगनवाड़ी केंद्र और लक्ष्मी नगर क्षेत्र के रहवासियों को हो रही परेशानी को लेकर प्रशासन तत्काल हरकत में आ गया। नायब तहसीलदार रविंद्र मंडलोई एवं तहसीलदार सुनील बागुल ने समस्या को गंभीरता से लेते हुए स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जल निकासी के लिए तत्काल राहत कार्य शुरू कराया। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए, जिसके बाद जेसीबी मशीन से पानी निकासी का कार्य तेज गति से शुरू किया गया। समस्या: आंगनवाड़ी तक पहुंचना हुआ मुश्किल, बस्ती में भर गया बारिश का पानी महादेव मंदिर के पीछे स्थित आंगनवाड़ी केंद्र के सामने बारिश का पानी लंबे समय से जमा होने के कारण पूरा क्षेत्र तालाब जैसा दिखाई देने लगा था। छोटे बच्चों, अभिभावकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा था। वहीं लक्ष्मी नगर में भी जल निकासी नहीं होने से बारिश का पानी घरों तक पहुंच गया, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित



हो रहा था।

कारण: जल निकासी व्यवस्था की अनदेखी बनी बड़ी वजह

ग्रामीणों का कहना था कि क्षेत्र में लंबे समय से नालियों की सफाई और जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। कई बार पंचायत और संबंधित अधिकारियों को शिकायतें देने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं हुआ। लगातार बारिश के कारण स्थिति और गंभीर होती चली गई। कार्रवाई: जेसीबी मशीन से बनाई गई नालियां, तेजी से निकाला गया पानी मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदारों के निर्देश पर जेसीबी व पोकलेन मशीन से लगाकर जल निकासी के लिए स्थायी नालियां बनाई गईं। प्रशासनिक टीम की निगरानी में तेजी से पानी निकासी का कार्य किया गया, जिससे जलभराव वाले क्षेत्रों में राहत मिलने लगी और आंगनवाड़ी केंद्र तथा आसपास के क्षेत्र में जमा पानी कम होने लगा।



प्रशासनिक पहल: अधिकारियों ने मौके पर रहकर कराई कार्रवाई

नायब तहसीलदार रविंद्र मंडलोई एवं सुनील बागुल ने स्वयं पूरे कार्य की निगरानी की। उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को जल निकासी कार्य में तेजी लाने और प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रशासन की सक्रियता से राहत कार्य बिना किसी विलंब के शुरू हो सका, आवागमन हेतु रेलवे ने जो सीसी रोड़ बनाया था हालात देख कर उसे भी तुड़वा कर नाली खुदवाई और पानी निकासी के लिए पाईप डाले जाएंगे

पुलिस की भूमिका

थाना प्रभारी के नेतृत्व में संभाली व्यवस्था, हटवाया जाम जलभराव की समस्या को लेकर ग्रामीणों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान

खकनार थाना प्रभारी अभिषेक जाधव अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखी और प्रशासनिक कार्रवाई में सहयोग किया। पुलिसकर्मी सुनील धुर्वे, शंकर लोने ने सड़क पर लगे जाम को हटवाकर यातायात को सुचारु कराया, जिससे दोनों ओर फंसे वाहनों की आवाजाही सामान्य हो सकी। पुलिस और प्रशासन के बेहतर समन्वय से स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण बनी रही और राहत कार्य निर्बाध रूप से जारी रहा।

ग्रामीणों की प्रतिक्रिया

कार्रवाई से मिली राहत, अब स्थायी समाधान की उम्मीद प्रशासन की त्वरित कार्रवाई के बाद ग्रामीणों ने राहत महसूस की। लोगों का कहना है कि लंबे समय से बनी समस्या पर अब कार्रवाई शुरू हुई है, जिससे जलभराव कम होने लगा है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से मांग की कि अस्थायी व्यवस्था के बजाय स्थायी जल निकासी योजना तैयार कर भविष्य में ऐसी समस्या की पुनरावृत्ति रोकी जाए। समाधान: स्थायी ड्रेनेज व्यवस्था और नियमित सफाई की जरूरत ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि तुकईथड़ के संवेदनशील क्षेत्रों का सर्वे कर स्थायी ड्रेनेज प्रणाली विकसित की जाए। साथ ही वर्षा ऋतु से पहले नालियों की नियमित सफाई और रखरखाव सुनिश्चित किया जाए, ताकि हर वर्ष लोगों को जलभराव और आवागमन की परेशानी का सामना न करना पड़े।

ढीमरखेड़ा पुलिस ने 48 घंटे में किया हत्या का खुलासा



नवल किशोर

कटनी। ढीमरखेड़ा थाना पुलिस ने हत्या के एक मामले में कार्रवाई करते हुए वारदात के 48 घंटे के अंदर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मामले के एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देश एवं मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य तथा एसडीओपी आकांक्षा चतुर्वेदी के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक महिमा रघुवंशी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार, 28 जुलाई 2026 को ग्राम खम्हरिया निवासी सुखबरा बाई की शिकायत पर थाना ढीमरखेड़ा में मारपीट का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की

गई थी। जांच के दौरान घायल प्रहलाद कोल की 29 जुलाई को उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इसके बाद प्रकरण में हत्या सहित अन्य संबंधित धाराओं का इजाफा किया गया विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपियों विदेशी उर्फ परदेशी कोल, रामरतन कोल एवं कुलसिया बाई कोल निवासी ग्राम खम्हरिया को 30 जुलाई को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मामले के एक अन्य आरोपी की पुलिस द्वारा लगातार तलाश की जा रही है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक महिमा रघुवंशी, उपनिरीक्षक जयपाल सिंह, उपनिरीक्षक विजेंद्र तिवारी, प्रधान आरक्षक दीपक श्रीवास, आरक्षक पंकज सिंह, देवेंद्र अहिरवार, अजय धुर्वे एवं गंधर्व सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

बरही पुलिस ने 20 से 25 लाख के सोने और चांदी के गहनों की चोरी का किया खुलासा मुख्य आरोपी गिरफ्तार

नवल किशोर

कटनी। बरही थाना पुलिस ने 20 से 25 लाख रुपये की बड़ी चोरी का खुलासा करते हुए करीब 25 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण बरामद कर लिए हैं। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसके तीन साथी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। वारदात में प्रयुक्त स्विफ्ट कार भी पुलिस ने जब्त कर ली है। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य एवं एसडीओपी विजयराघवगढ़ वीरेंद्र धावें के मार्गदर्शन में गठित टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।

पुलिस के अनुसार 23 जुलाई को बरही निवासी प्रमोद लखेरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दोपहर के समय अज्ञात चोर उनके घर का पिछला दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए और तिजोरी में रखे सोने-चांदी के जेवर तथा 80 हजार रुपये नकद चोरी कर ले गए। चोरी गए सामान की कुल कीमत 20 से 25 लाख रुपये बताई गई थी। घटनास्थल से जुटाए गए तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने संदेही



बनुसकोर पारधी तक पहुंच बनाई। लगातार तलाश के बाद उसे हिरापुर पारधी टोला, बरही से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने अपने साथियों छुपे राजा पारधी, दंगा पारधी और कचरु पारधी के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपी की निशानदेही पर ग्राम खिरहनी पारधी टोला से चोरी के करीब 25 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए गए। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त सफेद रंग की स्विफ्ट कार भी जब्त कर ली है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक अरविन्द चौबे उपनिरीक्षक नरेश झारिया, उपनिरीक्षक अरुण पाल सिंह, प्रधान आरक्षक नरेंद्र पटेल, आरक्षक अमित सिंह, रूपेंद्र, रामकृष्ण पटेल तथा साइबर सेल के अजय साकेत।



रणजीत टाइम्स कार्यालय में 15 अगस्त विशेषांक एवं विज्ञापन अभियान को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक संपन्न। सभी टीम सदस्यों ने पूर्ण सहयोग एवं बेहतर कार्य के संकल्प के साथ अभियान को सफल बनाने का विश्वास व्यक्त किया।

खंडवा में दो दिन से झमाझम बारिश, शहर हुआ जलमग्न

खंडवा: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के चलते शहर की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। पानी भरने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है और लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी हो रही है। बस स्टैंड और अन्य प्रमुख चौराहों पर भी पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों को पैदल चलने में भी मुश्किल हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश जारी



रहने की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरी सावधानी बरतने की अपील की है। प्रशासन द्वारा जलभराव वाले क्षेत्रों में राहत कार्य भी शुरू कर दिया गया है।

बरबसपुर में नई शराब दुकान के लोकार्पण का होगा विरोध, पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर का खुला ऐलान



कोरबा। बरबसपुर में प्रस्तावित नई शराब दुकान के लोकार्पण को लेकर राजनीति गरमा गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने खुला ऐलान करते हुए कहा है कि यदि शनिवार को आबकारी मंत्री लखन लाल देवांगन नई शराब दुकान के लोकार्पण के लिए बरबसपुर पहुंचते हैं, तो वे स्वयं मौके पर पहुंचकर इसका विरोध करेंगे। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने कहा कि क्षेत्र के अनेक लोग नई शराब दुकान खोले जाने के विरोध में हैं और उनकी

जनभावनाओं की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और वे स्थानीय लोगों के साथ लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे। पूर्व गृह मंत्री के इस बयान के बाद बरबसपुर का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। अब सभी की नजरें शनिवार को होने वाले लोकार्पण कार्यक्रम और संभावित विरोध प्रदर्शन पर टिकी हैं। विरोध की घोषणा के मद्देनजर प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

शिवपुरी के पूर्व पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदोरिया बने डीआईजी, पुलिस महकमे में खुशी की लहर

त्रिषि गोस्वामी

शिवपुरी के पूर्व एसपी रहे तेज-तरार आईपीएस अधिकारी रघुवंश सिंह भदोरिया को पदोन्नत कर डीआईजी (DIG) बनाया गया है। इससे पहले वे अलीराजपुर जिले में पुलिस अधीक्षक (SP) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, जहाँ उनकी कार्यशैली और जन-कल्याणकारी नवाचारों की खासी सराहना हुई थी। उनकी इस उपलब्धि से उनके गृह क्षेत्र और शिवपुरी जिले के शुभचिंतकों व पुलिस परिवार में हर्ष का माहौल है।

अनुशासित और जन-सरोकार वाली कार्यशैली

शिवपुरी जिले में अपने कार्यकाल के दौरान आईपीएस रघुवंश सिंह भदोरिया ने अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया था। स्मैक, अवैध शराब और अवैध रेत के कारोबार पर नकेल कसने में उनकी भूमिका को आज भी शिवपुरीवासी याद करते हैं। इसके अलावा, आम जनता और पीड़ितों के प्रति उनकी संवेदनशीलता उन्हें हमेशा से एक जनप्रिय पुलिस अधिकारी बनाती रही है। अलीराजपुर एसपी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने स्थानीय जनजातीय अंचल में जागरूकता



अभियानों, यातायात सुधार और 'अपना मानसे अपनी पुलिस' जैसे सकारात्मक संवाद कार्यक्रमों के जरिए पुलिस और जनता के बीच की दूरी को पाटने का सराहनीय कार्य किया। "अपराधियों के प्रति सख्त और पीड़ितों के लिए पूरी संवेदना—यही रघुवंश सिंह भदोरिया की पुलिसिंग का मूलमंत्र रहा है।" शुभकामनाएं एक कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित और मृदुभाषी पुलिस अधिकारी के रूप में पहचान बनाने वाले भदोरिया के डीआईजी बनने पर इष्ट-मित्रों, सहकर्मियों और नागरिकों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

जब छात्रों के बीच घुटनों के बल बैठे कलेक्टर... और मुस्फुराहटों से भर उठी कक्षा



नवल किशोर

कटनी । प्रेमनगर स्थित सीडब्ल्यूएसएन (विशेष आवश्यकता वाले बच्चों) के छात्रावास में शुक्रवार को संवेदनशीलता, आत्मीयता और प्रेरणा का ऐसा दृश्य बना, जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी जब छात्रावास पहुंचे तो उन्होंने औपचारिकता से दूरी बनाते हुए सीधे छात्रों की कक्षा में पहुंचकर घुटनों के बल बैठकर उनसे संवाद किया। इस

आत्मीय व्यवहार ने छात्रों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी और कुछ ही क्षणों में पूरा वातावरण अपनत्व से भर उठा। कलेक्टर श्री तिवारी ने विशेष आवश्यकता वाले इन छात्रों से उनकी पढ़ाई, रुचियों और भविष्य के सपनों के बारे में बात की।

छात्रों ने भी बिना किसी झिझक के पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने ज्ञान और कौशल का प्रदर्शन किया। यह संवाद केवल प्रश्न और उत्तर का नहीं, बल्कि विश्वास और प्रेरणा का संवाद बन गया।

'डिजिटल पहल लाई रफ्तार: नामांतरण प्रकरणों के निराकरण में 51% की वृद्धि, जुलाई में 162 प्रकरणों का निपटारा'

नवल किशोर

कटनी । नगर निगम की राजस्व सेवाओं को पारदर्शी, तेज और नागरिक-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन नामांतरण व्यवस्था के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। सतत मॉनिटरिंग और समय-सीमा में निराकरण के निर्देशों के फलस्वरूप राजस्व शाखा की कार्यकुशलता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

जुलाई में 51% अधिक प्रकरणों का निराकरण

निगमायुक्त के निर्देशों के बाद माह जुलाई 2026 में कुल 162 नामांतरण प्रकरणों का निराकरण किया गया है। यह आंकड़ा विगत माहों की तुलना में लगभग 51 प्रतिशत अधिक है। ऑनलाइन प्रविष्टि और समयबद्ध प्रक्रिया से फाइलों के लंबित रहने की समस्या कम हुई है और नागरिकों को त्वरित राहत मिल रही है।

चार माह में 476 प्रकरणों का निपटारा

राजस्व अधिकारी श्री जागेश्वर



प्रसाद पाठक ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से 30 जुलाई 2026 तक निगम कार्यालय में कुल 479 नवीन नामांतरण के प्रकरण प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त पिछले वित्तीय वर्ष के 155 प्रकरण भी लंबित थे। इस प्रकार कुल 634 प्रकरणों में से अब तक 476 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। शेष 158 प्रकरणों को ऑनलाइन दर्ज कर निर्धारित समय-सीमा में निराकरण की कार्यवाही प्रचलित है।

पारदर्शिता और नागरिक सुविधा को प्राथमिकता

निगमायुक्त सुश्री परिहार ने इस

उपलब्धि के बाद व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निगम कार्यालय में प्राप्त होने वाले प्रत्येक नामांतरण आवेदन की अनिवार्य ऑनलाइन प्रविष्टि की जाए और निर्धारित समय-सीमा में उसका निराकरण सुनिश्चित किया जाए। ऑनलाइन प्रणाली से न केवल प्रक्रियाएं सरल हुई हैं, बल्कि मानवीय हस्तक्षेप और बिचौलियों की भूमिका भी कम हुई है। आवेदक अब घर बैठे अपने प्रकरण की स्थिति देख सकते हैं।

नागरिक-अनुकूल शासन की दिशा में बड़ा कदम

निगमायुक्त ने कहा कि निगम का लक्ष्य है कि नागरिकों को बिना परेशानी, बिना देरी के बुनियादी सेवाएं उपलब्ध हों। नामांतरण जैसी सेवा का समय पर निराकरण होने से निगम के राजस्व में वृद्धि होगी और उस राशि का उपयोग शहर के विकास कार्यों में किया जा सकेगा। निगम प्रशासन का यह प्रयास "सुशासन और पारदर्शिता" की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका लाभ सीधे आम नागरिकों को मिल रहा है।

आगामी पर्वों की तैयारियों में जुटा निगम, विद्युत व्यवस्थाओं की महापौर ने की समीक्षा

नवल किशोर

कटनी। वर्तमान वर्षा ऋतु एवं आगामी सावन, रक्षाबंधन सहित विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक पर्वों के दौरान श्रद्धालुओं एवं नागरिकों को सुरक्षित, सुगम एवं निर्बाध आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर निगम की विद्युत शाखा के कार्यों की समीक्षा बैठक बुधवार को महापौर प्रीति संजीव सूरि की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में शहर की विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था को लेकर विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। महापौर श्रीमती सूरि ने अधिकारियों से कहा कि आगामी पर्वों के दौरान शहर के प्रमुख मंदिरों, धार्मिक स्थलों, मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक स्थलों पर पर्याप्त एवं गुणवत्तापूर्ण प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि श्रद्धालुओं एवं आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए सभी

आवश्यक विद्युत सामग्री एवं संसाधनों की उपलब्धता पहले से सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। समीक्षा के दौरान बंद पड़े विद्युत प्वाइंटों को शीघ्र चालू कराने, आवश्यक स्थानों पर विद्युत पोलों में तार खिंचवाने, मंदिरों एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट लगाने तथा विद्युत व्यवस्था से संबंधित लंबित कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। साथ ही यह भी कहा गया कि पर्वों के दौरान

किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या उत्पन्न होने पर उसका तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में सहायक यंत्री आदेश जैन, उपयंत्री मोना करेरा एवं शैलेन्द्र प्यासी सहित विद्युत शाखा के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने महापौर को विद्युत शाखा द्वारा संचालित कार्यों की प्रगति से अवगत कराया, जिस पर महापौर ने नागरिक सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी व्यवस्थाओं को समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए।





वेटलिफ्टिंग में 8वां पदक

लवप्रीत 1KG से गोल्ड से चूके, सीमा ने डिस्कस थ्रो में दिलाया कांस्य

नई दिल्ली। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को वेटलिफ्टिंग में गुरुवार (30 जुलाई) को 8वां पदक मिला। लवप्रीत सिंह ने 110+ किलोग्राम भारवर्ग में रजत पदक दिलाया। सीमा कालीरमन ने महिलाओं की डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता।

भारत ने अबतक 17 पदक अपने नाम किए हैं। वह 3 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य के साथ पदक तालिका में 10वें नंबर पर है। ग्लासगो में भारत ने वेटलिफ्टिंग में अबतक एक गोल्ड, छह सिल्वर और एक ब्रॉन्ज जीता है।

लवप्रीत ने अपने करियर का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने 176 किलोग्राम स्नैच के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ा और कुल 388 किलोग्राम (176+212) उठाकर गोल्ड मेडल जीता। भारतीय एथलीट न्यूजीलैंड के डेविड एंड्रयू लिटी से सिर्फ एक किलोग्राम पीछे रहे, जिन्होंने कुल 389 किलोग्राम उठाकर गोल्ड मेडल जीता। स्नैच के बाद 10 किलोग्राम की बढ़त बनाने के बाद पंजाब के वेटलिफ्टर का पलड़ा भारी दिख रहा था।

स्वर्ण से चूक गए लवप्रीत

लिटी ने क्लीन एंड जर्क में शानदार वापसी की और अंतिम प्रायस में 223 किलोग्राम का वजन उठाकर गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

लवप्रीत को शीर्ष पर पहुंचने के लिए 217 किलोग्राम वजन उठाने की जरूरत थी। उन्होंने कोशिश की, लेकिन लिफ्ट पूरी नहीं कर पाए। बता दें कि बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में लवप्रीत के ब्रॉन्ज मेडल जीता था।

भारत 10वें पर खिसका, ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर

● नाइजीरिया 5वें पर, यहां देखें पदक तालिका

नई दिल्ली। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के 17 पदक हो गए हैं, लेकिन वह पदक तालिका में 10वें नंबर पर खिसक गया है। भारत ने अबतक 3 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। ग्लासगो में आजोजित खेलों में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा बरकरार है। वह 51 स्वर्ण, 24 रजत और 35 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर है। इंग्लैंड 65 पदकों के साथ दूसरे नंबर पर है। उसने 15 स्वर्ण, 30 रजत और 20 कांस्य पदक जीता है। कनाडा 45 पदकों के साथ तीसरे नंबर पर है। स्कॉटलैंड ने 25 पदक जीते हैं। उन्होंने 9 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक जीते हैं। नाइजीरिया ने 16 पदक जीते हैं। 8 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। दक्षिण अफ्रीका के 23 पदक हैं। उन्होंने 6 स्वर्ण, 9 रजत और 8 कांस्य पदक जीता है। मलेशिया 12 पदकों के साथ 7वें नंबर पर है। उसने 6 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं।

भारत नीचे गिरा

न्यूजीलैंड 21 पदकों के साथ 8वें नंबर पर है। 5 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक के साथ 8वें नंबर पर है। जमैका 8 पदकों के साथ 9वें नंबर पर है। 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हैं। पदक तालिका में स्थान स्वर्ण जीतने से तय होता है। यही कारण है कि भारत 17 पदकों के बाद भी 8वें पर खिसक गया।

क्रिकेट
विश्व कप
2027

साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया होंगे मेजबान

12 शहरों में होंगे 54 मैच



नई दिल्ली। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ऐलान किया है कि 2027 में होने वाले पुरुष वनडे वर्ल्ड कप 12 शहरों में खेले जाएंगे। यह वर्ल्ड कप 24 साल में पहली बार दक्षिणी अफ्रीकी देशों में होगा। दक्षिण अफ्रीका के आठ शहर, जिम्बाब्वे के तीन और नामीबिया की राजधानी विंडहोक में कुल 54 मैच खेले जाएंगे। तीनों देश टूर्नामेंट के सह-मेजबान हैं। इससे पहले 2003 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या में वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था।

साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग, सेंचुरियन, डरबन, गकेबरहा, कुगोम्पो सिटी, केपटाउन, पार्ल और ब्लोमफॉन्टेन में 2027 वर्ल्ड कप के दौरान 54 मैचों में से ज्यादातर मैच होंगे। फाइनल वांडरर्स या न्यूलैंड्स में होगा। जिम्बाब्वे में हरारे, बुलावायो और विक्टोरिया फॉल्स के बीच सात से 10 मैच खेले जाएंगे और नामीबिया में विंडहोक भी कम से कम तीन मैचों की मेजबानी करेगा। बेनोनी और पोर्टचेफस्ट्रूम को वार्म-अप वेन्यू के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और नामीबिया के साथ वर्ल्ड कप क्वालिफायर को-होस्ट करने की संभावना है। टूर्नामेंट के 4 अक्टूबर से 21 नवंबर 2027 तक आयोजित होने की संभावना है।

- साउथ अफ्रीका के मैदान- वांडरर्स स्टेडियम (जोहान्सबर्ग), सेंचुरियन (त्शवाने), न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड (केपटाउन), किंग्समीड क्रिकेट ग्राउंड (डरबन), सेंट जॉर्ज पार्क (गकेबरहा), मंगांग ओवल (ब्लोमफॉन्टेन), बोलेन्ड पार्क (पार्ल) और बफेलो पार्क (कुगोम्पो सिटी, जिसे पहले ईस्ट लंदन के नाम से जाना जाता था)।
- जिम्बाब्वे के मैदान- हरारे स्पोर्ट्स क्लब (हरारे), क्वींस स्पोर्ट्स क्लब (बुलावायो), फाले मोसी-ओआ-तुन्या इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (विक्टोरिया फॉल्स)।
- नामीबिया- नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड (विंडहोक)।
- 2003 वर्ल्ड कप के बाद साउथ अफ्रीका ने इन आईसीसी टूर्नामेंट्स की मेजबानी की- 2003 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या ने 8वें मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। इसके बाद से साउथ अफ्रीका ने कई बड़े आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट किए हैं। इनमें पहला मेन्स टी20 वर्ल्ड कप (2007), विमेंस अंडर-20 वर्ल्ड कप (2023), अंडर-19 मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप (2020 और 2024) और अंडर-19 विमेंस टी20 वर्ल्ड कप (2023) शामिल हैं।

भारत-ब्राजील के बीच होगा फुटबॉल मैच

IFF का बड़ा ऐलान; कब और कहां खेला जाएगा मुकाबला?



कब और कहां खेला जाएगा यह मुकाबला?

नई दिल्ली। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का हाल ही में समापन हुआ है। भारत में भी फुटबॉल का जुनून चरम पर था। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय फुटबॉल फैंस ने भारतीय टीम के ना होने पर दुख भी जताया था। अब भारतीय फुटबॉल फैंस के पास अपने देश की टीम को चीयर करने का मौका होगा। भारत और ब्राजील के बीच कोलकाता में एक बेहतरीन मुकाबला होने जा रहा है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (द्वुस्र) ने गुरुवार को भारत और ब्राजील के बीच होने वाले ऐतिहासिक मुकाबले का ऐलान किया है।

ऑस्ट्रेलिया में ब्राजील की टीम पहला मुकाबला 25 सितंबर को ब्रिस्बेन में खेलेगी। इसके बाद ब्राजील की टीम भारत के दौरे पर आएगी और इस विंडो का तीसरा मुकाबला खेलेगी। भारत और ब्राजील के बीच यह मैच कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में 3 अक्टूबर 2026 को खेला जाएगा। यह दोनों देशों की टीमों के बीच एक फ्रेंडली मैच होगा।

द्वुस्र के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने इस मैच को लेकर कहा, 'ब्राजील जैसी टीम का अपने देश में स्वागत करना एक शानदार पल होगा। साथ ही यह पल भारतीय फुटबॉल के इतिहास का एक अनमोल क्षण होगा।' जबकि ब्राजील फुटबॉल महासंघ की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया, 'यह एक स्पेशल मैच होगा उस देश के साथ जहां ब्राजील की टीम का सबसे बड़ा फैनबेस है। यहां के फैंस ने सालों से ब्राजील के फुटबॉल इतिहास को पैशन के साथ फॉलो किया है।'

थाम लीजिए दिल!

2027 क्रिकेट विश्व कप के 12 मेजबान शहरों का ऐलान

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने 2027 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए 12 मेजबान शहरों और स्टेडियमों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त

मेजबानी में अक्टूबर-नवंबर 2027 में खेला जाएगा। खास बात यह है कि 24 साल बाद क्रिकेट विश्व कप की अफ्रीका में वापसी हो रही है।

इन 12 स्थानों पर होंगे मुकाबले

- »» दक्षिण अफ्रीका (8)
- »» जोहान्सबर्ग - वांडरर्स स्टेडियम
- »» त्शवाने (सेंचुरियन) - सुपरस्पोर्ट पार्क
- »» केपटाउन - न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड

- »» डरबन - किंग्समीड
- »» गकेबेर्हा - सेंट जॉर्ज पार्क
- »» ब्लोमफॉन्टेन - मंगांग ओवल
- »» पार्ल - बोलेन्ड पार्क
- »» कुगोम्पो (पूर्वी लंदन) - बफेलो पार्क
- »» जिम्बाब्वे (3)
- »» हरारे - हरारे स्पोर्ट्स क्लब
- »» बुलावायो - क्वींस स्पोर्ट्स क्लब
- »» विक्टोरिया फॉल्स - फाले

मोसी-ओआ-तुन्या

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम

- »» नामीबिया (1)
 - »» विंडहोक - नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड
- इस बार टूर्नामेंट में 14 टीमों भाग लेंगी और प्रतियोगिता नए तीन-चरणीय प्रारूप में खेली जाएगी। कुल 57 मुकाबले होंगे। पहले चरण में निचली रैंक वाली तीन टीमों खेलेंगी।

सरकार ने एक किमी भी नहीं बनाई

● ट्राइबल हॉस्टल बनाने में भी नहीं ली रुचि, एमपी में केंद्र की स्कीम के हाल

भोपाल (नप्र)। केंद्र सरकार द्वारा आदिवासी बहुल इलाकों में समग्र विकास के लिए शुरू किए गए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के क्रियान्वयन को लेकर संसद में आंकड़े सामने आए हैं। राज्यसभा में जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उड्डे ने देश भर के 63,843 जनजातीय बहुल गांवों में चल रही मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की राज्यवार रिपोर्ट पेश की।

संसदीय रिपोर्ट के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में देश में सबसे अधिक 30,865.92 लाख (308.65 करोड़) रुपये की निधि आवंटित की गई है। राज्य में नल-जल योजना, ग्रामीण आवास, एलपीजी वितरण, मत्स्य पालन और पशुधन विकास के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है, जबकि मोबाइल नेटवर्क, सड़क निर्माण और जनजातीय छात्रावासों के निर्माण के मोर्चे पर प्रोग्रेस स्लो है।

नल जल योजना में 54 प्रतिशत टारगेट पूरा हुआ

मध्य प्रदेश में 11,309 लक्षित गांवों में से 6,112 गांवों (54.05 प्रतिशत) तक नल-जल सुविधा पहुंच चुकी है, जो 47वें के राष्ट्रीय औसत से बेहतर है और राज्य देश में निचले क्रम से 12वें स्थान पर है। वहीं, योजना में सबसे फिसड्डी प्रदर्शन केरल का रहा, जहां 89 में से महज 1 गांव (1.00 प्रतिशत) में ही नल से जल पहुंच पाया है। केरल के अलावा त्रिपुरा (11.33 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (18.71 प्रतिशत), राजस्थान (19.57 प्रतिशत) और मणिपुर (22.99 प्रतिशत) भी बेहद धीमी गति के साथ देश के सबसे फिसड्डी राज्यों में शामिल हैं।



एमपी में 41 फीसदी आवास बने

ग्रामीण आवास के मामले में मध्य प्रदेश को देश में सबसे ज्यादा 3,68,395 मकानों की स्वीकृति मिली, जिनमें से 1,52,309 मकान (41.34 प्रतिशत) बनकर तैयार हो चुके हैं और राज्य निचले क्रम से 14वें स्थान पर है। इस योजना में पश्चिम बंगाल का प्रदर्शन पूरे देश में सबसे निराशाजनक और फिसड्डी रहा, जहां 48,232 स्वीकृत मकानों में से केवल 61 मकान (0.12 प्रतिशत) ही बन सके हैं। केरल (4.24 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (13.01 प्रतिशत), कर्नाटक (13.32 प्रतिशत) और झारखंड (15.41 प्रतिशत) भी देश में सबसे कम मकान बनाने वाले फिसड्डी राज्यों में शुमार हैं।

39 प्रतिशत आदिवासी परिवारों तक ही बिजली पहुंची

ऑन-ग्रिड घरेलू बिजली वितरण में मध्य प्रदेश के 59,822 लक्षित परिवारों में से 23,416 (39.14 प्रतिशत) को बिजली से जोड़ा गया, जो 34 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से अधिक है और राज्य निचले क्रम से 9वें स्थान पर है।

इस मोर्चे पर जम्मू-कश्मीर (0.00 प्रतिशत) और झारखंड (0.00 प्रतिशत) सबसे फिसड्डी साबित हुए हैं, जहां स्वीकृत परिवारों में से एक भी घर तक बिजली नहीं पहुंची है। इनके साथ उत्तर प्रदेश (1.74 प्रतिशत), राजस्थान (13.97 प्रतिशत) और हिमाचल प्रदेश (15.00 प्रतिशत) का प्रदर्शन भी बेहद कमजोर दर्ज किया गया है।

● मोबाइल नेटवर्क में भी एमपी देश में पांचवें नंबर पर- मध्य प्रदेश के 776 नेटवर्क विहीन जनजातीय गांवों में से 571 गांवों (73.58 प्रतिशत) में ही मोबाइल टावर लग सके हैं, जिससे एमपी और उत्तर प्रदेश (73.58 प्रतिशत) संयुक्त रूप से देश में नीचे से 5वें स्थान पर खड़े हैं। इस सुविधा में सबसे फिसड्डी स्थिति जम्मू-कश्मीर की रही, जहां लक्षित गांवों में से केवल 20.00 प्रतिशत गांवों में ही मोबाइल टावर स्थापित हो सके हैं। इसके अलावा गोवा (40.00 प्रतिशत), कर्नाटक (63.16 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (67.64 प्रतिशत) भी मोबाइल कनेक्टिविटी के मामले में सबसे पीछे छूटने वाले राज्यों में शामिल हैं।

● छात्रावास बनाने में एमपी सबसे फिसड्डी- जनजातीय विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बनाने में मध्य प्रदेश की स्थिति निराशाजनक है, जहां स्वीकृत 104 छात्रावासों के लिए 10,740 लाख रुपये जारी होने के बावजूद जमीनी स्तर पर 0.00 प्रतिशत काम पूरा हुआ है। हालांकि, यह फिसड्डीपन केवल एमपी तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के 22 राज्यों में निर्माण कार्य 0 प्रतिशत पर अटका हुआ है। राजस्थान (58 स्वीकृत), अरुणाचल प्रदेश (45), मणिपुर (44) और छत्तीसगढ़ (42) जैसे राज्य भी 0 प्रतिशत निर्माण पूर्णता के साथ सबसे फिसड्डी श्रेणी में खड़े हैं, जबकि देश भर में केवल असम ही एकमात्र राज्य है जहां 4 छात्रावास बनकर तैयार हुए हैं।

● 345 सड़कें मंजूर हुईं, बनी एक भी नहीं- जनजातीय बसावटों को सड़क संपर्क से जोड़ने के मामले में मध्य प्रदेश में 913 किलोमीटर की 345 सड़कें स्वीकृत की गई थीं, लेकिन जमीनी स्तर पर निर्माण पूरा होने की दर शून्य (0.00 प्रतिशत) रही है। देश भर में सड़क निर्माण के मामले में 13 राज्य पूरी तरह फिसड्डी साबित हुए हैं, जहां एक किलोमीटर सड़क का निर्माण भी पूरा नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश के साथ-साथ ओडिशा (629 किमी स्वीकृत), जम्मू-कश्मीर (512 किमी), राजस्थान (291 किमी) और हिमाचल प्रदेश (285 किमी) जैसे राज्य 0 किमी पूर्णता के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में हैं, जबकि पूरे देश में केवल छत्तीसगढ़ ही 3.9 किमी सड़क पूरी कर सका है।

यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास का पानी पीने लायक नहीं

भोपाल में गैस त्रासदी पीड़ित संगठनों ने 63 सैंपल लिए; इनमें से 43 में फीकल कोलीफॉर्म मिला



भोपाल (नप्र)। भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस त्रासदी पीड़ितों के चार संगठनों ने शुक्रवार को शहर में सफाई किए जा रहे पेयजल को लेकर गंभीर आरोप लगाए। संगठनों का दावा है कि भोपाल नगर निगम कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास के इलाकों में सीवेज से दूषित पानी की आपूर्ति कर रहा है, जिससे इंदौर

के भागीरथपुरा जैसी स्थिति बनने का खतरा पैदा हो गया है।

संगठनों ने प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की जांच कराई, जिसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक की। रिपोर्ट के मुताबिक जांचे गए पानी के करीब 70 प्रतिशत नमूनों में फीकल कोलीफॉर्म (मल से जुड़े बैक्टीरिया) पाए गए।

दूषित पानी से बढ़ रही गंभीर बीमारियां

संगठनों का आरोप है कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से सटे इलाकों के लोग लंबे समय से सीवेज से दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। इसके कारण दस्त, उल्टी, टाइफाइड समेत जलजनित बीमारियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि कई परिवार एक साथ बीमार पड़ रहे हैं और निजी क्लिनिकों में टाइफाइड के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की अध्यक्ष रशीदा बी ने बताया कि साल 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे से यहां का भूजल जहरीले रसायनों और भारी धातुओं से प्रदूषित हो चुका है। इसके बाद कोर्ट ने प्रभावित क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाकर लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।

आठ साल से शिकायत, फिर भी नहीं बिछी सीवर लाइन

भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशनभोगी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष बालकृष्ण नामदेव ने कहा कि अगस्त 2018 में पेयजल में मल मिलने की शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल नगर निगम को प्रभावित क्षेत्रों में सीवर लाइन और बेहतर ड्रेनेज व्यवस्था विकसित करने का आदेश दिया था। नगर निगम ने तीन महीने में काम पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आठ साल बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग- भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना धीगरा ने दूषित पेयजल की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाला जा रहा है।

भागीरथपुरा जैसी घटना का इंतजार करने के बजाय दौड़ियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में सीवर और ड्रेनेज परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए तथा पेयजल की गुणवत्ता की स्वतंत्र निगरानी की व्यवस्था भी तत्काल शुरू की जाए।

तोते को दूढ़कर लाने वाले को 50 हजार का इनाम

ग्वालियर में तोते के बिछड़ने से दादी-पोती ने खाना छोड़ा, शहरभर में करा रहे मुनादी



ग्वालियर (नप्र)। कहते हैं रिश्ते सिर्फ इंसानों से नहीं बनते, कभी-कभी एक बेजुबान भी परिवार का ऐसा हिस्सा बन जाता है कि उसके बिना घर सूना लगने लगता है। ग्वालियर के अलकापुरी-कलेक्ट्रेट रोड स्थित एनजी ग्रांड में रहने वाले अनिल ओझा का परिवार इन दिनों ऐसी ही पीड़ा से गुजर रहा है। उनके घर का चहेता तोता 'शाकुंतला' उर्फ मिट्टू (मादा) तीन दिन पहले उड़ गई। तब से घर में सन्नाटा पसरा है। हर दरवाजे पर दस्तक दी जा रही है, हर गली और हर कॉलोनी में उसकी तलाश हो रही है। उसे सुरक्षित वापस लाने वाले के लिए परिवार ने 50 हजार रुपये के इनाम की घोषणा भी की है। अनिल ओझा भावुक होकर कहते हैं। 50 हजार हमारे लिए मायने नहीं रखते। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी वही होगी, जब मिट्टू फिर से घर लौट आएगी। जिस दिन वह वापस आएगी, उसी दिन मेरी मां और बेटी के चेहरे पर खोई हुई मुस्कान भी लौट आएगी। ई-रिक्शा से मिट्टू दूढ़कर लाने वाले को इनाम देने की अपील की जा रही।

एक साल में बन गया घर का सबसे प्यारा सदस्य

अनिल ओझा बताते हैं कि करीब एक वर्ष पहले शाकुंतला उनके घर आई थी। उसने धीरे-धीरे पूरे परिवार का दिल जीत लिया। उसे कभी पिंजरे में कैद नहीं रखा गया। वह पूरे घर में बेफिक्र होकर घूमती थी, परिवार के लोगों की आवाज सुनते ही उनके कंधे या हाथ पर आ बैठती थी। उसके बिना घर की सुबह और शाम की कल्पना भी मुश्किल थी।